

## न्याय की परिकल्पना व्यवस्था के स्वरूप पर निर्भर – बजरंगलाल

व्यवस्था न्याय की पूरक है। न्याय आवश्यकता है और व्यवस्था उसकी पूर्ति का माध्यम। वस्तु व्यवस्था का व्यावहारिक स्वरूप ही न्याय के गुण दोष को निर्धारित करता है। अधिकार के रूप में न्याय की पूर्ति बिना व्यवस्था के संभव नहीं दिखती अतएव व्यवस्था के दायित्व को गंभीरता से लेना नितान्त आवश्यक जान पड़ता है।

न्याय के आदर्शवादी दृष्टिकोण, अधिकारों और व्यवस्था के बीच एक संतुलन अनिवार्य है। न्याय की मूलभूत आवश्यकता के अनुसार यदि व्यवस्था की पूर्ति अथवा आचरण नहीं होता है तब व्यवस्था का दूषित होना लाजिमी है। इसके लिए न्याय की मांग के आधार पर व्यवस्था की मात्रा घटाई – बढ़ाई जाती है किसी भी परिस्थिति में न्याय की मांग को व्यवस्था के लिए पूरा करना संभव नहीं हुआ तो व्यवस्था धीरे धीरे अव्यवस्था में बदल जायेगी।

वर्तमान भारत में न्याय और व्यवस्था के बीच कोई संतुलन नहीं दिखता। भारत में इसका अनुपात इस प्रकार है कि कोई व्यक्ति एक सौ लोगा को भोजन पर आमंत्रित कर जबकि उसकी क्षमता मात्र पन्द्रह लोगों को भोजन कराकर शेष 85 लोगों को भूखा रख दिया जायें जबकि अगले दौर में नये व पुराने 185 लोगों के बीच फिर मात्र 15 लोगों को भोजन बंटने की स्थिति हो तब स्वाभाविक है कि अव्यवस्था/कुव्यवस्था के साथ छीना झपटी लूटमार होने की संभावना भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में कुछ सामर्थ्यवान तो भोजन कर सकेंगे शेष सामान्य लोग भूखे पेट चुपचाप घर लौट जायेंगे। यह स्थिति व्यवस्था के स्वरूप में बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि आवश्यकता और पूर्ति के बीच कोई संतुलन नहीं है। स्वाभाविक है कि व्यवस्था और न्याय के बीच पनपा यह असंतुलन मूर्खता का परिचायक है या हमारी धूर्तता का। निश्चित रूप से यह हमारी बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती है।

भारत में न्याय की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। नित नयी-नयी समस्याएँ/मांगे उठायी जाती है और व्यवस्था से इसकी पूर्ति का आश्वासन मिलते ही वह मांग न्याय में बदलती जाती है। यह नया आश्वासन पूर्व से ही न्याय और व्यवस्था के बीच चल रहे असंतुलन को बढ़ाता है। तब तक कोई मांग और आश्वासन का क्रम आ जाता है जो इस असंतुलन को और भी अधिक बढ़ाता है। कुछ समय तक असंतुलन को और भी अधिक बढ़ाता है। कुछ समय तक अव्यवस्था होती है और फिर कुव्यवस्था में बदल जाती है। यह क्रम सम्पूर्ण भारत में पचपन वर्षों से चल रहा है। पहले यह असंतुलन कम था किन्तु अब धीरे धीरे बहुत अधिक हो गया है।

न्याय और व्यवस्था के बीच इस असंतुलन के चलते बिना व्यवस्था की मात्रा का आकलन किये न्याय की मांग करना और आश्वासन देना भारत में एक फैशन बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों से भारत में न्याय देने की नई की नई परंपरा भी विकसित हो रही है और यह प्रणाली व्यवस्था को बहुत क्षति पहुंचा रही है। उदाहरण स्वरूप सौ लोगा की लाईन में पन्द्रह लोगा की ही भोजन मिलना निश्चित है और व्यवस्था यह बनाई गयी कि लाईन से ही प्रत्येक को भोजन मिलेगा, तो स्वाभाविक है कि पीछे की लाईन वाले भूखे रह जायेंगे और इसका कोई उपाय भी नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय बीच में ही हस्तक्षेप करके किसी बीच वाले को भोजन देने का आदेश शुरू कर दे तब व्यवस्था का क्या होगा ? संकट में पड़ो व्यवस्था और अधिक संकटग्रस्त हो जायेगी। प्रायः पिछले कुछ वर्षों से सीधे न्याय दिलाने का एक फैशन बन गई। व्यवस्था तोड़कर न्याय दिलाने के प्रयत्न से प्रशंसा भी खूब मिलती है और प्रचार भी किन्तु यह नहीं सोचा जाता कि इस पद्धति का परिणाम कितना भयंकर हो रहा है। पहले से लंबित और चरमरा रही व्यवस्था कितनी संकट में आती जा रही है राजनैतिक दल न्याय/मांगों की पूर्ति का आश्वासन देते हैं और न्यायालय उस आश्वासन को न्याय मानकर उसकी पूर्ति का आदेश दे देता है। दोनों अपनी अपनी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा लेते हैं। नित व्यवस्था कैसे सुधरे इससे न नेताओं को मतलब है न ही न्यायालयों को। मानवाधिकार संगठन तथा अन्य अनेक तथा कथित समाजिक संस्थाओं या उससे जुड़े लोगों का तो यह धंधा ही बन गया है।

हमारे राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा के पात्र हैं। उनकी सादगी चरित्र ईमानदारी और धर्म निरपेक्षता उनका स्वभाव है नाटक नहीं। इसके बावजूद राष्ट्रपति के रूप में उनकी कार्य प्रणाली पर अवश्य विचार करने की आवश्यकता है। दैनिक भास्कर में 19 जनवरी 2005 को प्रकाशित एक खबर के अनुसार महामहिम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम कुछ दिन पूर्व लखनऊ दौर पर थे तब एक शासकीय सेवा में कार्यरत नर्स ने सुरक्षा घेरा तोड़ कर अपनी फरियाद राष्ट्रपति जी को सुनाई अथवा सुनानी चाही। सुरक्षा घेरा तोड़ने तथा बिना अनुमति के राष्ट्रपति से शिकायत करने को अनुशासन हीनता मानकर उसे नौकरी से निकाल दिया गया जिस पर राष्ट्रपति जी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उ.प्र. सरकार को पत्र लिखा। अनेक लोगों ने राष्ट्रपति के इस प्रयास कि प्रशंसा को किन्तु मुझे इस प्रयास में कुछ संकट दिखाई देता है। यहा दो प्रश्न उठते हैं। प्रथम क्या राष्ट्रपति को ऐसा करने का अधिकार था ? दूसरा क्या राष्ट्रपति को ऐसा करना उचित था? ये दोनों ही प्रश्न जटिल हैं। मेरे विचार में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह नियम तोड़ कर न्याय दे सके किन्तु आचार संहिता के दृष्टिकोण से यह उचित नहीं। भारत की संपूर्ण व्यवस्था राष्ट्रपति के नाम पर चलती है। यदि व्यवस्था किसी फरियादी को न्याय देने में बाधक है तो राष्ट्रपति को भी यह अधिकार कहा से प्राप्त हुआ या उनको ऐसा क्यों करना चाहिए कि वे व्यवस्था में परिवर्तन करने के स्थान पर व्यवस्था को तोड़कर न्याय देने की पहल करें जिस अधिकारी ने उस नर्स को सुरक्षा घेरा तोड़ने से रोका और जिसने उसे अनशासनहीनता के लिए

दण्डित किया उन अधिकारियों ने तो व्यवस्था का पालन किया जिसके लिए वे बधाई पात्र हो सकते हैं किन्तु राष्ट्रपति जी के कृत्य का किस श्रेणी में रखा जाय यह एक विचारणीय प्रश्न है। यदि राष्ट्रपति जी की सहृदयता कही आड आती है तो भविष्य में सुरक्षा घेरा न तोड़ने की व्यवस्था और बिना अनुमति उच्च अधिकारियों से मिलने पर प्रतिबन्ध जैसे—कानून हटा लें। यहा राष्ट्रपति जी की दो भूमिकाएँ हो सकती हैं प्रथम सहृदय अब्दुल कलाम की दूसरी भारत के महामहिम राष्ट्रपति की अब्दुल कलाम को दया, करुणा, त्याग और न्याय करने का व्यक्तिगत रूप से अधिकार हो सकता है परन्तु राष्ट्रपति के रूप में वे पूरी तरह से उस व्यवस्था से बंधे हैं जो उनके स्वयं के मार्गदर्शक तथा नाम से बनाई गई है यदि वे दया, करुणा, त्याग और न्याय के कारण निर्मित व्यवस्था को तोड़ते हैं तो वे व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। यह सस्ती लोकप्रियता भी हो सकती है और उनकी महानता भी किन्तु राष्ट्रपति के रूप में उनका वह व्यवहार देश को क्षति ही पहुँचाएगा। इसी परिपेक्ष्य में अनेक राजनेता/उच्च अधिकारी भी वहा वही लूटने के क्रम में प्रायः व्यवस्था तोड़ने के अभ्यस्त हो गये हैं। वस्तुतः वह भारत की व्यवस्था कमजोर ही कर रहे हैं।

आज कल न्यायालय की भूमिका बहुत मानवीय और संवेदनशील हो गयी है एक साधारण पोस्ट कार्ड मात्र लिख देने को भी वह याचिका मानकार कार्यवाही शुरू कर देता है वास्तव में यह बहुत आदर्श स्थिति है किन्तु क्या ऐसा करना उचित है क्या न्यायालय को व्यवस्था के तहत ऐसा करना चाहिए जो न्यायालय का क्या औचित्य है इस तरह दया दिखाने का। यदि विलम्ब का कारण व्यवस्था का अभाव है तो इस पर व्यवस्था तोड़कर आदर्श प्रस्तुत करने से व्यवस्था और क्षीण होती जायेगी। जब देश व्यवस्था के संकट में गुजर रहा हो तब न्यायालय को व्यवस्था कमजोर करने से बचना चाहिए।

आज भारत लगातार अव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है कुछ राजनैतिक दल तो सोची समझी रणनीति के अन्तर्गत नित नई नई आदर्श मांगे प्रस्तुत करते हैं। उनके लिये आन्दोलन करते हैं उन्हें न्याय संगत होने का जामा पहनाते हैं और अन्त में किसी ना किसी तरह उन्हें आशिक या पूरी की पूरी मनवा लेते हैं। ऐसी न्याय संगत मांगे व्यवस्था को और कमजोर करती हैं हमारे अनेक उच्च या सर्वोच्च पदाधिकारी भी प्रायः यह भूल जाते हैं कि व्यवस्था का दायित्व संभालने के बाद उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन और दायित्वाधिकारी जीवन में घालमेल करना व्यवस्था को नुकसान पहुँचाना है यदि वे एक सा दुहरा जीवन नहीं जी सकते तो उन्हें ऐसे पद स्वीकार ही नहीं करना चाहिये कोई न्यायाधीश यदि न्याय के स्थान पर दया करना व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है पद का अधिकार नहीं।

सार्वजनिक बैठकों में भी कमोवेश यही स्थिति है वहां व्यवस्था होती ही नहीं। व्यवस्थापक बार बार रोकते हैं किन्तु वक्ता कुछ भी और कितना भी बोल चले जाते हैं कोई विचार विमर्श होता नहीं और कोर ग्रुप द्वारा पारित प्रस्ताव पढ कर तथा हाथ उठाकर पारित हो जाता है मैं ऐसे मामलों में बहुत अलग तरह से व्यवस्था का अधिकतम पालन करने का पक्षधर हूँ। मेरी बैठकों में प्रायः ही कोई नाराज होकर चला जाता है किन्तु मैं व्यवस्था तोड़ने की अनुमति नहीं देता जबकि मैं व्यवस्था नहीं तोड़ता मुझे अब तक इस व्यवस्था की प्रतिबद्धता से बहुत लाभ हुआ है। इससे समय की बचत होती है कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है तथा निगम/कानून का पालन करने वालों के साथ न्याय होता है।

मैं मानता हूँ कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के कारण यहाँ व्यवस्था से ही न्याय मजबूत किया जा सकता है। व्यवस्था का ठीक-ठीक आकलन करके उसी अनुपात में न्याय की घोषणा भी करनी चाहिए और दायित्व भी स्वीकार करना चाहिए हमारे उच्च पदाधिकारियों को भी स्वयं व्यवस्था का पालन करने और दूसरों से व्यवस्था पालन करने को आदत डालनी चाहिए क्योंकि वर्तमान भारत में जो अव्यवस्था और कुव्यवस्था का खतरा मंडरा रहा है उसका मुख्य कारण न्याय और व्यवस्था के बीच असंतुलन ही है जिसको तत्काल संतुलित करना चाहिए।

## —प्रश्नोत्तर—

### 1. श्री ज्ञानेन्द्र मिश्र नैनी इलाहाबाद

**प्रश्न—** देश के संभावित भावी कर्णधार राहुल गांधी ने कांग्रेस चिन्तन शिविर में पार्टी के आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की आलोचना सुनने से इन्कार करके राजनैतिक असहिष्णुता का परिचय दिया है। उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोधी स्वर इस तरह दबाने की तानाशाही मनोवृत्ति से बचना चाहिये। अन्यथा स्वर्गीय संजय गांधी और राहुल गांधी में क्या अन्तर रह जायगा।

राहुल जी ने उस शिविर में पेप्सीकोला और कोकाकोला शीतलपेय कम्पनियों का यह कह कर बचाव किया कि उसमें कीटनाशक जान बुझकर नहीं मिलाये गये थे बल्कि दूषित भूगर्भ जल का परिणाम मात्र है। क्या राहुल जी को यह कहना चाहिये था? यदि यह सच भी हो तो उन्हें इस तरह विदेशी कम्पनियों का पक्ष लेना शोभा नहीं देता? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस संबंध में आपके विचार क्या हैं?

**उत्तर—** आपने इस संबंध में गंभीर प्रश्न उठाया है। मैंने दैनिक नवभारत की बाइस जनवरी के अंक में सम्पादकीय के रूप में बेबाक टिप्पणी के अन्तर्गत भी ऐसे ही विचार पढे हैं। समाचार पत्र के लेखक की राय भी वैसी ही है जैसी आपकी।

राहुल जी ने कांग्रेस के चिन्तन शिविर में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की आलोचना सुनने वाले को किन परिस्थितियों में रोका उन स्थितियों को जाने बिना कुछ टिप्पणी करना ठीक नहीं। मेरा अपना अनुभव है कि कई लोग समय की महत्ता विषय चर्चा की प्राथमिकताएँ उनके कथन कि सारगर्भिता आदि का

विचार किये बिना बोलते रहते हैं। या अनावश्यक एक ही बात को बार बार बोलते हैं जिन्हें जब रोका जाता है तो उन्हें बुरा लगता है। सहिष्णुता का अर्थ अव्यवस्था नहीं माना जाना चाहिए मैं नहीं समझता कि राहुल जी ने वक्ताओं को इसलिये अपनी बात कहने से रोका होगा कि वे आर्थिक सुधारों के विरुद्ध बोल रहे हैं और यदि किसी मुद्दे पर अन्तिम रूप में कोई नीति बन जाने और घोषित हो जाने के बाद भी ऐसे विरोध की रट लगाये हो तो उन्हें व्यवस्थित करने हेतु रोकने से मैं सहमत हूँ। स्थिति क्या थी। मैं नहीं कह सकता।

किन्तु प्रश्नकर्ता तथा नवभारत के सम्पादकीय का दूसरा अंश बिल्कुल विपरीत है। प्रश्न का पहला भाग कार्यकर्ताओं की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्षधर है दूसरा अंश राहुल गांधी की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोधी। क्या राहुल गांधी को वहा वह नहीं बताना चाहिये जो वे सच समझते हैं। कोकाकोला और पेप्सीकोला में कीटनाशक का होना कितना यथार्थ है और कितना भावनात्मक यह बात तो अवश्य विचारी जानी चाहिए। मैं विदेशी उत्पादों के प्रयोग के विरुद्ध हूँ क्योंकि इससे स्थानीय रोजगार के अवसर घटते हैं किन्तु मैं इस विरोध को भावनात्मक स्वरूप प्रदान करने के पक्ष में नहीं। कुछ भारतीय कम्पनियों से धन लेकर या राजनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर जो विरोध हाता ह। वह पेशा भले ही हो किन्तु विरोध नहीं। जब भाजपा विरोध में हाती है और कांग्रेस सत्ता में तब दोनों की इस संबंध में जो भाषा होती है वह भाषा सत्ता बदलते ही बदल जाती है इस फेर बदल को कोई अर्थ नहीं है साथ ही उस विरोध को भी कोई अर्थ नहीं है जिन्हें सब काम छोड़कर विरोध करना ही है। मैं उस विरोध को महत्वपूर्ण मानता हूँ। जो गुण दोष की समीक्षा की सच्चाई न दिखकर विदेशी कम्पनियों के विरोध की ठेकेदारी का अधिक आभास होता है। जो ठीक नहीं है।

मैं पेप्सीकोला कोकाकोला के प्रदूषण क विषय में अब तक सच्चाई नहीं जान सका कि बात क्या है? यदि राहुल जी की बात सच है तो फिर भारतीय शीतल पेयों में भी वैसा ही प्रदूषण होना चाहिये। यदि स्थानीय भारतीय शीतल पेय प्रदूषण रहित है तो राहुल गांधी की बात गलत है। उन्हें इस तरह विदेशी कम्पनियों का पक्ष नहीं लेना चाहिये और यदि भारतीय शीतल पेयों में भी प्रदूषण वैसा ही जैसा कोला पेय में तो फिर प्रदूषण के नाम पर विरोध क्यों है? मैं दोनों के सच जाने बिना कुछ कह नहीं सकता क्योंकि कम्पनियों का बनाने और बेचने की छूट देकर गलत करता है। मैं भी उससे सहमत था। मैंने बहुत पता किया तो मालूम हुआ कि रासायनिक खाद विदेशी कम्पनियों को यही बनाने की छूट देने से आयत की समस्या नहीं रहेगी। मुझे इनका भी तर्क ठीक जँचा। दोनों पक्ष एक साथ बैठकर चर्चा करें तब तो आम लोग जाने कि सच्चाई क्या है दानों पक्ष पृथक पृथक प्रचार करें तो समझना बहुत कठिन होता है और यदि एक पक्ष अपने कथन के पक्ष मैं वैचारिक तर्क के स्थान पर भावनात्मक प्रचार का सहारा लेने लगे तो निर्णय और भी कठिन होता है।

मेरे एक सर्वोदयी मित्र ने हमारी दिल्ली की बैठक में कोकाकोला आने पर आपत्ति प्रकट की। मैं स्वयं इन सबका उपयोग नहीं करता। अतः मैंने भी भविष्य के लिये सर्तक किया। किन्तु मेरे मित्र तो साक्षात् दुर्वासा ही हो गये और कोला वापस करने की बहुत जिद करने लगे। मैं उनकी जिद के समक्ष झुक गया किन्तु मैंने अपने सर्वोदय मित्र पर कटाक्ष किया कि एक विदेशी महिला भारत में विवाह करके आपकी नजर में इतनी स्वदेशी बन जाती है और भूल से की गई आयोजकों की गलती के लिये आप आसमान सर पर उठा रहे हैं। तब वे मित्र चुप हुए। मुझे इन आतिवादी सिद्धान्तों से दुख होता है। मैं चाहता हूँ कि वैचारिक मुद्दों को भावनात्मक स्वरूप देने से बचा जाय।

आपने मुझे प्रश्न पूछा जिसका मैंने अपनी समझ से उत्तर दिया। मैं भी कुछ प्रश्न भेज रहा हूँ। आप मित्रों से उम्मीद है कि आप उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा शान्त करेंगे।

(1) विदेशी कम्पनियों के शीतल पेय और स्वदेशी कम्पनियों के शीतल पेयों के बीच हानिकारक तत्वों में समानता है या अन्तर। यदि अन्तर है तो क्यों विदेशी कम्पनियों उस अन्तर को दूर क्यों नहीं कर पाती। यदि अन्तर नहीं है तो विदेशी विरोध के लिये कीटनाशक प्रयोग को मुद्दा बनाना कितना उचित है और कितना न्यायोचित ?

(2) स्वदेशी आन्दोलन ग्यारह मौलिक समस्याओं में से किन किन का समाधान है। यह आंदोलन हमारी प्राथमिकताओं में सबसे उपर होना चाहिए या आन्दोलन के अन्य विषयों के साथ।

(3) हम भारत की स्वदेशी व्यवस्था का जो आर्थिक स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें मूलभूत आवश्यकता को तथा श्रम निर्मित सभी प्रकार की वस्तुओं को पूरी तरह कर मुक्त करके कृत्रिम उर्जा पर भारी कर को सिफारिश शामिल है इससे आवागमन मंहगा होगा छोटे उद्योग मजबूत होंगे और इसके परिणाम स्वरूप विदेशी कम्पनियों स्वत फेल हो जायेंगी। विदेशी कम्पनियों पर से पूरी तरह कानूनी या सामाजिक विरोध को समाप्त करके यदि ऐसा आर्थिक समाधान कर दे कि सांप भी मर जाये और लाठी भी बची रहे तो आप इससे कितना सहमत हैं?

(4) स्वदेशी आन्दोलन कितना भावनात्मक है और कितना तर्क संगत आशा है कि पाठक इस संबंध में उत्तर देंगे।

2. 2/2/ 89 ग प्रश्न श्री विश्वनाथ सिंह जी हिल्सा नालंदा बिहार,

प्रश्न— आपने कई बार लिखा है कि व्यवस्था परिवर्तन के चरित्र सुधरेगा। मैं व्यवस्था परिवर्तन के पक्ष में हूँ। मैं पूरी तरह इस काम में आपका सहयोग करूँगा। किन्तु व्यवस्था बदलने से चरित्र बदलेगा। यह असत्य मैं कैसे स्वीकार कर लूँ ? मेरे विचार में हृदय परिवर्तन से ही चरित्र निर्माण संभव है। जब तक हृदय परिवर्तन नहीं होगा तब तक न चरित्र बदलेगा न संस्कार और न ही स्वाभाव। आप इस प्रश्न का विस्तृत समाधान करें और अपने कथन में संशोधन करें।

### 3. डा. अनुपम नैनीताल

**प्रश्न—** ज्ञानत्व अंक छयासी में व्यवस्था और चरित्र को समानुपाती बताया गया है मेरे विचार में इसमें संशोधन की आवश्यकता है। चरित्र निर्माण कभी सरकारी कानूनों से नहीं हुआ करता और न ही समाज से होता है। चरित्र तो परिवार व्यवस्था से बनता है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था ने परिवार को अलग करके व्यवस्था बनानी शुरू की जो पूरी तरह गलत था इससे परिवार व्यवस्था टूटी, परिवार भावना टूटी और व्यक्ति उच्चश्रखल होता चला गया। आज कल हम देख रहे हैं कि बलात्कार के बाद हत्या का प्रचलन बढ़ रहा है क्योंकि बिना गवाह के न्यायालय सजा दे नहीं सकता। अतः सबूत नष्ट करने का पहले प्रयास होता है आप प्रधान मंत्री राष्ट्रपति या न्यायाधीश बदल कर भी बिना सबूत के सजा कैसे दे सकते हैं। अतः व्यवस्था बदलने से चरित्र बदल जायेगा।

लोग अपराध बन्द कर देंगे अपराधियों को सजा मिलने लगेगी यह तर्क मेरी समझ में नहीं आया और अधिक स्पष्ट करने की कृपा करे।

उत्तर – आपके प्रश्न अत्यन्त गंभीर और जटिल होने से विस्तृत समीक्षा करनी होगी। भारत के वैचारिक धरातल पर एक धुंध छाई है। भावनात्मक प्रचार ने विचार मथन की प्रक्रिया को अवरुद्ध कर दिया है। प्रत्येक विषय को भावनात्मक रूप देने की गलत प्रणाली विकसित हो गई है। अनेक शब्दों ने अपने अर्थ बदल दिये हैं। अनेक शब्दों की परिभाषाएँ विपरीत अर्थ निकालने लगी हैं। हमारे समक्ष बहुत दिक्कत आती है जब चर्चा में हमें क ख ग से बात शुरू करनी पड़ती है। किन्तु समाज में फ़ैली धुंध दूर करने हेतु यह सब करना उचित भी है आवश्यक भी।

व्यवस्था और सत्ता के बीच अन्तर करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जज बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती क्योंकि व्यवस्था तो एक प्रणाली है। जिसके आधार पर ये लोग काम करते हैं। व्यवस्था धार्मिक व्यवस्था पारिवारिक व्यवस्था आदि। सबके मार्ग भी भिन्न होते हैं तथा परिणाम भी। सभी एक दूसरे से बिल्कुल पृथक पृथक होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं।

चरित्र भी तीन प्रकार का होता है। 1. अच्छा 2. सामान्य 3. बुरा। धर्म समाज और परिवार चरित्र का अच्छी दिशा में ले जाने में प्रेरक और सहायक होते हैं। ये मरे चरित्र को रोकने में हृदय परिवर्तन ईश्वरीय भय, सामाजिक भय, पारिवारिक भय आदि का सहारा लेते हैं किन्तु इन सबकी मुख्य भूमिका होती है चरित्र निर्माण। शासन या राजनैतिक व्यवस्था की सिर्फ एक ही भूमिका होती है कि एक निश्चित सीमा के अधिक चरित्र पतन के कार्य को बल पूर्वक रोकने का प्रयास। इस तरह संवैधानिक व्यवस्था ही एक मात्र शक्ति है जो आपराधिक चरित्र पतन रोक सकती है। कानून कभी भी सामान्य व्यक्ति को चरित्रवान नहीं बना सकता किन्तु कानून सामान्य व्यक्ति के चरित्र पतन को रोक सकता है क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था का तो काम ही यही है।

जब कानून चरित्र निर्माण करने लगे और चरित्र पतन रोकने का दायित्व समाज पर छोड़ने लगे तो यह बिल्कुल विपरीत स्थिति होती है। इसका सीधा परिणाम होता है चरित्र पतन क्योंकि कानूनों से चरित्र निर्माण ही नहीं सकता और न ही बिना कानून के अपराध रूक सकते हैं। यदि एसी संवैधानिक व्यवस्था चल रही हो तो उक्त व्यवस्था ही चरित्र पतन के लिये उत्तरदायी है और व्यवस्था को बदलना ही उसका विकल्प है। भारत में दहेज, छुआछूत, शराब, गांजा, बालविवाह, बालश्रम आदि सामाजिक बुराइयों को कानून से रोकने का निरंतर प्रयास हो रहा है दूसरी और डकैती हिंसा आदि आपराधिक बुराइयों को रोकने के लिये हृदय परिवर्तन की बातें कही जाती हैं। यह विपरीत संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह बदले बिना हम कोई चरित्र निर्माण नहीं कर सकते क्योंकि समाज धर्म और राजनैतिक व्यवस्था वर्ष में पच्चीस प्रतिशत तक चरित्र पतन करती है तो कुल मिलाकर पन्द्रह प्रतिशत चरित्र गिरता ही है जैसे कि अभी हो रहा है। हम यदि चरित्र उपर ले जाना चाहते हैं तो संवैधानिक व्यवस्था को इस तरह बदलना होगा कि शासन और कानूनों का हस्तक्षेप समाज धर्म और परिवार में कम से कम हो जाय तथा शासन अपराध नियंत्रण तक सीमित रहकर उसे सफलता पूर्वक सम्पन्न कर लें। मेरे विचार में चरित्र उत्थान के उद्देश्य में सबसे बड़ा बाधा है। यह राजनैतिक व्यवस्था और इसे बदलना ही इसका एकमात्र मार्ग है।

भारत के संवैधानिक स्वरूप में परिवार प्रणाली को कहीं स्वीकृति या मान्यता नहीं है। व्यक्ति को सीधा राज्य से जोड़ दिया गया और राज्य को केन्द्र से। परिवार और गांव की न कोई संवैधानिक रचना की गई न ही उनके अधिकारों को परिभाषित किया गया परिवार के पारिवारिक विषयों में भी शासन कानून बनाने लगा। स्त्री किसी पति की पत्नी रहते हुए भी पति के विरुद्ध बलात्कार का प्रकरण दर्ज करा सकती है। ऐसे ऐसे कानून बन रहे हैं। सप्ताह में एक दिन महिलाओं को भोजन बनाने की छूट मिले ऐसे अनावश्यक प्रस्तावों पर संसद बहस करती है राजनैतिक शक्ति को कुछ परिवार तक समेट कर रखने के दुष्प्रकार के लिये राजनीति में महिला आरक्षण का बिल लाया जाता है। स्त्री या पुरुष को व्यक्ति रूप में सीधा राजनैतिक व्यवस्था से जोड़ा गया है। बीच से पारिवारिक व्यवस्था को नकारते हुए। यदि ये इतने ही महिलाओं के प्रति सहृदय हैं। तो महिला आरक्षण बिल में यह अंश क्यों नहीं जोड़ते कि किसी परिवार का एक ही सदस्य सांसद या विधायक बन सकता है। परिवार की एक स्पष्ट परिभाषा बना दी जाय। परिवार से बाहर की महिला को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आदि परिवार व्यवस्था को संवैधानिक व्यवस्था में अमान्य और कमजोर करके महिला को एक वर्ग के रूप में खड़ा करना एक घातक कदम है। इस संबंध में आगे अलग से लेख जायगा।

इस तरह अब भी मैं आश्वस्त हूँ कि संवैधानिक व्यवस्था में आमूल्य चूल बदलाव या व्यापक संशोधन करके ही हम चरित्र पतन को भी रोक सकते हैं और चरित्र निर्माण भी कर सकते हैं इसलिये हमने व्यवस्था परिवर्तन को प्रथम आवश्यकता घोषित किया है।

### 3. श्री वेद व्यथित संयोजक सामाजिक न्याय मंच वल्लभगढ

पिछले दो तीन माह से मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ। मने आपसे कुछ गंभीर प्रश्न किये थे आपने उत्तर नही दिया। यदि आप निरुत्तर हों तो हमें सूचित कर दे जिससे हम प्रतिक्रिया तो न कर। आपको न तो उत्तर देने में विलम्ब करना चाहिए न ही पलायन।

उत्तर— हमारा उद्देश्य समाज में फली असत्य धारणाओं पर एक सार्थक बहस प्रारंभ करना है। जिससे सत्य और झूठ की पहचान सुविधाजनक हो। इस तरह जो लोग मेरे विचारों से सहमत है। उनके पत्रों का हम कोई उत्तर नही देते किन्तु जो लोग उन विचारों से असहमत है। उनका उत्तर अवश्य देते है। साधारण प्रश्ना का उत्तर ता मैं स्वयं ही दे दिया करता हूँ किन्तु गंभीर टिप्पणियों पर हम कई मित्र बैठकर लम्बी चर्चा करते है। यदि ऐसी टिप्पणी के विषय पर अन्य लोगों के विचार भी आने की निकट भविष्य म संभावना हो तो ऐसे विद्वानों के पत्रों की प्रतीक्षा भी करते है। उत्तर लिखने के बाद भी छपकर आप तक पहुँचने में एक माह और लग जाता है दिल्ली के भाई रमेश शर्मा जी का पत्र मिले ढाई माह हो गये। आपके पत्रों को भी इतना समय हो गया होगा। आप दोनों के पत्र बिल्कुल ही एक दूसरे के विपरीत थे किन्तु इतने गंभीर कि लिखने के पूर्व और लिखने के बाद भी काफी कुछ विद्वानों से मंथन करना पडा। कई शब्द कटे और कई जुड़ क्योकि आप दोना के प्रश्नों का उत्तर सिर्फ आपके उत्तर तक सीमित न होकर व्यापक प्रतिक्रिया पैदा कर सकता था। अतः विलम्ब होना हमारा दोष नही बल्कि मजबूरी थी।

आपके प्रश्नों के उत्तर ज्ञान तत्व अंक अठासी में भेजे जा चुके है। मुझे पता है कि मेरे उत्तर के बाद कुछ लोग गंभीरता से विचार करेंगे। कुछ लोग प्रसन्न होंगे कि अच्छी आलोचना की है तो कुछ लोग बहुत नाराज होंगे कि बहुत कटु भाषा का प्रयोग है हमारी मजबूरी है कि हमें यह सब कुछ झेलना पडता है। आप विश्वास करिय कि मैं या मेरे साथी कोई जीत हार का खेल नही खेल रहे ह। न ही यह हम लोगों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। हम किसी संस्था या संगठन का काम भी नही कर रहे कि कोई लाभ हानि का आकलन है। हमारा कथन ठीक नही उसी क्षण हम अपने कथन में संशोधन कर लेते ह। किसी भी परिस्थिति में उत्तर देने से पलायन का न कोई स्वभाव है न आवश्यकता और न ही मजबूरी मैं माह में पन्द्रह दिन दिल्ली कार्यालय मे रहता हूँ। मेरा फोन नं. दोनों कार्यालय में 09425254192 है। आप फोन से चर्चा करके कभी दिल्ली आ भी सकते है। दिल्ली कार्यालय का पता है।

आर्य भूषण भारद्वाज, गीतांजली पब्लिक स्कूल के सामने भजनपुरा दिल्ली 110053,

### श्री रवीन्द्र सिंह तोमर संवाद सरोवर गुन्ना मध्यप्रदेश।

धनंजय और जाहिरा दोनों ही अशिक्षा के कारण कानूनी न्याय से वंचित रहे। यदि वे शिक्षित होते तो उनकी ऐसी हालत नही होती। आप भी चौदह वर्ष तक जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में रहे कैदी को सजा याफता नही मानते एवं और अधिक सजा को उचित कहते हैं। दूसरी और पल्टन मल्लाह को आजीवन कारावास और उसको हथियार बनाकर उससे हत्या कराने वाले को दोष मुक्त हो जाना भी हम प्रत्यक्ष ही देख रहे ह। गोडसे को हथियार बनाने वालों ने ही सन चौरासी में श्रीमती गांधी की हत्या कराकर उपभोक्ता संस्कृति और शहरीकरण को जन्म दिया और जन आन्दोलन को कागजों तक सीमित किया। कृपया इस संबंध में अपने विचार भेजे।

उत्तर— मैं आपकी शिक्षा और योग्यता के विषय में जानता हूँ और मानता हूँ कि आप बहुत अच्छे प्रश्न करने की क्षमता रखते है। किन्तु पिछले चार पाच वर्षों स प्राप्त आपके सभी प्रश्न यह प्रमाणित करते हैं कि आप किसी न किसी विचारधारा के हथियार के रूप में प्रयुक्त होते हैं अन्यथा कोई कारण है कि आप कही की ईट कही का रोडा जोडकर इस तरह बेसिर पैर के पश्न उठाते। आपके प्रत्येक पत्र में संघ शब्द छूट गया यद्यपि गोडपे शब्द आकर उस ओर इशारा कर गया। मेरा आपसे निवेदन है कि आप भले ही संघ विरोधी विचार धारा के हो किन्तु विचार प्रस्तुति में आपको तर्क पूर्ण शब्द चयन करना चाहिए न कि जबरदस्ती।

आपके आठ लाइन के पत्र में ये चार मुद्दे शामिल है —

- (1) धनंजय निर्दोष था,
- (2) जाहिरा को भी न्याय नही मिला,
- (3) नियोगी हत्याकांड में हत्या कराने वाले निर्दोष छूट गये।
- (4) गांधी जी की हत्या करने में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल लोगों का ही इन्दिरा हत्या में हाथ था।

मुझे आश्चर्य है कि आप गुना में बैठे बैठे इतने गंभीर मामलों की इतनी सूक्ष्म सतह तक पहुच गये जबकि मैं पूरे वर्ष भर इतना बाहर भी घूमता हूँ और इतना व्यापक सम्पर्क है। किन्तु मैं आपके चार निष्कर्षों में से अब तक किसी के अन्तिम निष्कर्ष तक नही पहुँचा कि क्या सच है और क्या झुठ को बार बार बोलन में गोयबल्य को भी पीछ छोडने के प्रयास कर रहे हों वहाँ सत्य क्या है। यह बताना अत्यन्त कठिन काम है जो आप इतनी आसानी से कर रहे है कि आप पर भी संदेह होने लगता है।

आप हमेशा प्रश्न करते हैं इस बार मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि आप ऐसी कौन सी व्यवस्था करते जो पूरी तरह धनंजय, जाहिरा, इन्दिरा के हत्यारे और नियोगी हत्याकांड में अप्रत्यक्ष शामिल लोगों को ठीक से पहचान कर अपराधियों को सजा और निर्दोष को मुक्त करती ? क्या अखबारों में छपने या आप लोगों के कहने से निर्णय की व्यवस्था संभव है। यदि नहीं तो वह तरीका क्या हो? यह आप लिख भेजिये कि कानूनों में ऐसा फेरबदल करने से ठीक ठीक न्याय संभव है। यदि सुप्रीम कोर्ट से उपर भी कोई और कोर्ट रख दे और वह भी यही फैसला दे तो क्या आप उसे न्याय मान लेंगे? यदि धनंजय निर्दोष था और उसे फांसी हो गई तो व्यवस्था पूरी तरह दोषी है। किन्तु यदि धनंजय का अपराध फांसी लायक था किन्तु चौदह वर्ष जेल में रह जाने के कारण उसे फांसी न दी जावे इसमें मुझे कोई तर्क नजर नहीं आया। क्या बिना अपील किये या बिना पूरी सुनवाई किये ही फांसी दे दी जाये। यह धनंजय सुप्रीम कोर्ट से निर्दोष छूट जाता और आप चौदह वर्ष की यातना का प्रश्न उठाते तो कुछ तर्क संगत था किन्तु एक अपराधी को तत्काल फांसी न होकर चौदह वर्ष बाद फांसी हुई और यह विलम्ब अन्याय है यह मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि जिन लोगों ने अनावश्यक अपील करके धनंजय की फांसी मंद करवाई उन्हें दण्डित कराने का प्रयास करिये क्योंकि वे लोग बेचारे को अनावश्यक इतने दिनों तक जेल में रहने के कारण बने।

मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि आप प्रश्न करने के साथ साथ उत्तर भी सोचने का प्रयास करिये और गांधी हत्या को इन्दिरा गांधी हत्या से जाड़कर उपभोक्ता संस्कृति जैसे घिसे पिटे शब्दों के साथ तालमेल के बजाय स्पष्ट रूप से स्वतंत्र चिन्तन की आदत डालिये।

## 6. श्री महेश भाई, विजयोपुर, गोपालगंज बिहार,

ज्ञान तत्व अंक पचासी मिला। मेरे प्रश्न का आपने आकड़ों सहित उत्तर दिया। यह प्रश्नोत्तर अन्य पाठकों को भी ठीक दिशा दे सकेगा। इस प्रश्नोत्तर से यह सिद्ध होता है कि उपभोक्ता वादी सुविधाभोगी की एक छोटी सी जामात व्यवस्था की अव्यवस्था कितनी चालाकी से बनाये रखती हैं। सच्चाई यह है कि इस चालाक जामात का निहितार्थ आम आदमी निगल रहा है और ये वे उसे व्यवस्था की हरियाली दिखाकर भविष्य के गर्त में ढकेल रहे हैं। ये लोग सामाजिक न्याय के साम्प्रदायिकता का हवा खड़ा करके वास्तविकता की समझ ही पैदा नहीं होने देते। परिणाम स्वरूप यथा स्थिति मजबूत से मजबूत होती जा रही है। आम आदमी अपनी पेट की ज्वाला बुझाने के प्रयत्नों में व्यस्त है तो अनिल मुकेश अम्बानी अपने वर्चस्व के संघर्ष में व्यस्त है। ठाकुरदास बंग और बजरंगलाल यथा स्थिति तोड़ने के प्रयत्नों में व्यस्त और मस्त ह तो सुश्री निर्मला देशपांडे हरिजन सेवक संघ की सत्रह करोड़ की राशि की सुरक्षा तथा पाकिस्तान चीन यात्रा मैत्री यात्रा में लगी है। यह एक विडम्बना ही है कि अखबारों में प्रयत्न करके छपवाया जाता है कि गांधी कभी बन नहीं सकता और कृत्य सारे गांधी हत्या के होते हैं। मैं तो इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि ऊँची कुर्सी संवेदन हीन होकर यथा स्थिति को मजबूत करने में ही लगी है।

**उत्तर** मैं आपकी समीक्षा से पूरी तरह सहमत हूँ। भारत में उपभोक्ता वादी सविधा भोगियों की एक बहुत छोटी जामात ही है जो भौतिक विकास को अपना एकमात्र राष्ट्रीय एजेन्डा घोषित करके सम्पूर्ण भारत को उपभोक्ता वादी संस्कृति की ओर ढकेल रही है। यह टुकड़ों अपने राजनैतिक आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति के लिये सुविधाभोग की जो असीमित भूख पैदा कर रही है। वह समाज में वास्तविक समस्याओं से ध्यान हटाकर यथा स्थिति को लगातार मजबूत कर रही है। इस टुकड़ों में सभी पूँजीवादी और साम्यवादी जमातें शामिल हैं। दोनों दिन रात एक दूसरे के विरुद्ध तलवारे लिये टकराते रहते हैं। किन्तु शोषण के मामले में दोनों के स्वर एक समान है। मुझे आश्चर्य होता है कि एक रिक्शे वाला भी पेट्रोल और रसोई गैस की मूल्य वृद्धि का विरोध करता है किन्तु वह यह जानता ही नहीं कि उसके रिक्शे पर कितना भारी उत्पादन आर बिक्री कर लागाकर मूल्य वृद्धि की गई है। वह यह भी नहीं सोच पाता कि डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि से पेट्रोल डीजल चलित वाहनों का मंहगा आवागमन रिक्शा चालक के लिये वरदान है। उसे तो उसकी सारी समस्याएँ बताने का ठेका प्रत्यक्ष रूप से वामपंथियों और अप्रत्यक्ष रूप से दक्षिण पंथियों के पास है और दोनों ही ठेकेदार उसे दिनरात यही समझा रहे हैं कि डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि उसका रिक्शा चालन में हानिकर होगी इन लोगों ने हमारे गरीब लोगों को कृत्रिम उर्जा मूल्य कमी की एक ऐसी हड्डी दे दी जिसे चुस चुस कर अपने ही मुँह से निकल खून का स्वाद ये ले रहे हैं और इन दोनों की जयकार कर रहे हैं।

मेरे एक मित्र रवोन्द्र सिंह तोमर बार बार उपभोक्ता वादी संस्कृति का रोना भी रोते हैं और भौतिक विकास की प्राथमिकता की भी बात करते हैं। यदि आम नागरिकों में सड़क, पानी बिजली शिक्षा स्वास्थ्य जैसी भौतिक आवश्यकताओं की असीम भूख पैदा की गई तथा उक्त भूख पूरी करने के प्रयत्न भी हुए तो अन्य अनेक वास्तविक समस्याएँ भी नैपथ्य में चली जायेगी तथा उपभोक्तावादी संस्कृति भी मजबूर होगी। मैं नहीं समझता कि अन्य सभी समस्याओं को दरकिनार करके भौतिक विकास को ही एक मात्र लक्ष्य बनाने की वकालत और उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रचार प्रसार का रोना रोने के पीछे कौन सा नाटक काम करता है। भौतिक आवश्यकताओं की भूख पैदा करने और उसकी पूर्ति के निरंतर प्रयासों का स्वाभाविक परिणाम है उपभोक्ता संस्कृति विस्तार। या तो हमारे वामपंथी मित्र पूँजीवादी की भौतिक प्रगति की असीम भूख पैदा करने वाला नीति के साथ चलने से परहेज करें या उपभोक्ता संस्कृति विस्तार के विरोध का नाटक बन्द करें। मैं महसूस करता हूँ कि हमें भौतिक प्रगति और ग्यारह समस्याओं के समाधान के बीच कोई न कोई सामंजस्य स्थापित करना ही होगा और कोई मार्ग नहीं है।

मैं महसूस करता हूँ कि विचार मंथन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की गंभीर जरूरत है तभी इस यथा स्थिति सुदृढकरण के वामपंथी और दक्षिणपंथी षडयंत्र को तोड़ा जा सकेगा। आपकी और सक्रियता की अपेक्षा है।

## 7. श्री संतोष शर्मा बी.ए 57 शालीमार बाग दिल्ली 88

आपने छत्तीसगढ़ विधान सभा का चुनाव लड़ा होता तो जनता के बीच भी प्रचार होता और आप यदि चुने जाते ता अधिक दम से अपनी बात रख पाते। आपने नगर पंचायत का चुनाव लड़कर जो ठीक शुरुआत की उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया?

उत्तर— आपने जो प्रश्न किया है वह बहुत जटिल है मेरे अनेक मित्र ऐसे सुझाव देते हैं। हमारे उपाध्यक्ष अमरसिंह जी तो इस पर बहुत जोर देते ह। अतः इस मुद्दे पर विस्तृत समझ आवश्यक है।

व्यवस्था परिवर्तन और व्यवस्था में सुधार में बहुत अन्तर है। व्यवस्था में सुधार तभी संभव है जब व्यवस्थापकों की नीयत और नीतियों में से एक गडबड हो दोनों नहीं वर्तमान में दोनो गडबड है। अतः अब न तो व्यवस्था में कोई सुधार या संशोधन संभव है। न ही हम ऐसा कोई प्रयास कर रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन ही एक मात्र मार्ग है यह अन्तिम रूप से मान लिया गया है। हमने पांच अक्टूबर दो हजार चार से व्यवस्था परिवर्तन का एकसूत्रीय अभियान शुरू भी कर दिया है। राजनीति के माध्यम से व्यवस्था में सुधार तो किया जा सकता है किन्तु परिवर्तन नहीं क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन समाज शास्त्र का विषय है राजनीति शास्त्र का नहीं। राजनीति शास्त्र जब व्यवस्था के सुधार में असफल हो जाता है तथा भविष्य में भी सुधार की कोई संभावना नहीं दिखती तब व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता होती है और व्यवस्था परिवर्तन राजनीति शास्त्र की सीमाओं से निकलकर समाज शास्त्र का विषय बन जाता है भारतीय राजनीति ग्यारह समस्याओं में लगाता वृद्धि की दोषी है और भविष्य में उनमें से किसी एक के भी समाधान की उसके पास कोई योजना या संभावना नहीं है। तभी तो हम लोगों के व्यवस्था परिवर्तन को राजनीति से पृथक करके समाज के जिम्मे लिया है। मुझे खुशी है कि सर्वोदय ने भी इस बात को महसूस किया और ठाकुरदास जी बंग के माध्यम से इसमें अपनी सहभागिता दर्ज की है। भारत विकास संगम ने भी इस कार्य को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और भारत विकास संगम के प्रमुख श्री गोविन्दाचार्य जी ने राजनीति में शामिल होने का आडवाणी जी का आमंत्रण अस्वीकार कर दिया है। धीरे धीरे वे सब लोग जो राजनीति में रहकर निराश है वे व्यवस्था परिवर्तन के प्रयास में कूद पड़ेंगे। दूसरी ओर प्रसिद्ध जैन मुनि विनय सागर जी ने भी यह महसूस किया है कि अब समाज को राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन में हस्तक्षेप करना ही चाहिए इस समय जो लोग राजनैतिक उच्चश्रलता से आंख मूद कर संत परिपाटी की पुरानी लीक पर ही कायम है वे भूल कर रहे हैं विनय सागर जी ने भी व्यवस्था परिवर्तन के कार्य में कूदने का निश्चय किया है। ऐसे समय में मैं विधान सभा या लोक सभा का चुनाव लड़ूँ यह या तो मेरा स्वार्थ माना जायेगा या कायरता जो लोग व्यवस्था परिवर्तन का अंशभव मानते ह वे ही व्यवस्था में सुधार के लिए राजनीति में जाने की सोच सकते हैं मैं नहीं।

रामानुजगंज का नगर पंचायत अध्यक्ष बनना न कोई व्यवस्था सुधार के लिये था न व्यवस्था परिवर्तन के लिये। उद्देश्य सिर्फ यह प्रमाणित प्राप्त किये जा सकते ह मैं यदि अध्यक्ष न होकर पार्षद होता तो क्या कर लेता यदि छत्तीसगढ़ की जोगी सरकार या रमन सरकार मुझे कड्ड होकर रोक देती या बर्खास्त कर देती तो मैं क्या कर लेता मेरे पयोग की सफलता की तुलना विधायक या सांसद से करना बिल्कुल ही अनुपयुक्त है। रामानुजगंज शहर के अध्यक्ष के रूप में मैं वहां क लिये इतना अधिक शक्तिशाली था जितना आज भारत का प्रधानमंत्री भी नहीं है मैं अपने प्रयोग पूरी स्वेच्छा से करता था जनता समर्थन करती थी पार्षद भी मजबूरन समर्थन करते ही थे छत्तीसगढ़ के नगरपालिका कानून के अनुसार अध्यक्ष को पार्षद सर्व सम्मति से भी हटा नहीं सकते क्योंकि वह जनता द्वारा सीधे मतदान द्वारा चुना जाता है और जनता ही हटा सकती है। मान लिये कि मैं भारत का प्रधानमंत्री भी बन जाता तो मनमोहन सिंह जी के समान वामपंथिया के सामन या अटल जी के समान संघ परिवार के इर्द गिर्द चापलूसी करता रहता । यह बिल्कुल सच है कि व्यवस्था में किसी तरह का सुधार न प्रधानमंत्री कर सकते ह न राष्ट्रपति व्यवस्था को तो बदलना ही होगा और यह काम हम और आप जैसे सामाजिक चिन्तक ही कर सकते हं अतः आपसे निवेदन है कि आप भूलकर भी मुझे राजनैतिक दलदल की ओर आकृष्ट होने की सलाह न दें।

## 8. श्री मुरारीलाल अग्रवाल, संपादक सतयुग की वापसी, 34 मधुबन, अलवर 301001 राजस्थान

ज्ञान तत्व अंक छयासी मिला। आपके प्रयासों की दिशा तो ठीक है किन्तु परिणाम प्राप्त करने में बहुत विलम्ब दिखता है।

आजकल पंजाब केशरी में अश्विनी कुमार जी के सारगर्भित लेख आते हैं। इकतीस जनवरी से पांच फरवरी तक क लेख बहुत गंभीर हैं। आप पढ़ें तो लाभ होगा। आज की तात्कालिक आवश्यकता है कि इस बाबा छाप संविधान को बदला जाय। संविधान की धारा अठाइस अल्पसंख्यकों को अपने धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार का मौलिक अधिकार देती है। सब जानते हैं कि मुसलमान और इसाई हिन्दुत्व विरोधी धारणा रखते हैं किन्तु हमारा संविधान उन्हें ऐसी धारणा रखने का मौलिक अधिकार भी देता है। भारत के चरित्र पतन बहुत तीव्र गति से हो रहा है। धर्म निरपेक्षता के नाम पर बेइमान लोग शासन कर रहे ह। मेरी सलाह है कि आप और काम छोड़कर संविधान परिवर्तन के कार्य में लग जावें।

उत्तर — छत्तीसगढ़ में पंजाब केसरी मिलना बहुत कठिन है यदि उक्त पांच दिनों के अंक हो तो आप मुझे सिर्फ उक्त लेखों की फोटो कापी भिजवाने की कृपा करे। मैं भी दिल्ली में प्रयास करूंगा।

भारतीय संविधान अपने उद्देश्य में विफल हुआ। उसमें व्यापक संशोधन की आवश्यकता है। मैं पूरी तरह सहमत भी हूँ और प्रयत्नशील भी किन्तु क्या संशोधन हो यह तय करना आसान नहीं। धर्म और संस्कृति के मामले में दो गुट बने हुए हैं (1) संघ परिवार समर्थक (2) संघ परिवार विरोधी। वास्तव में दानों गुट ही धर्म निरपेक्ष नहीं है एक हिन्दू राष्ट्र की मांग करता है और दूसरा विरोध। संघ समर्थक गुट समान नागरिक अहिंसा के नाम पर समान आचार संहिता का पक्षधर है तो दूसरा समान आचार संहिता के विराध के नाम पर समान नागरिक संहिता का भी विराधी है। उन दोनों ही पेशेवर गिरोह हैं दोनों का उद्देश्य है राजनैतिक सत्ता प्राप्त करना और मुखौटा है धर्म या धर्म निरपेक्षता। ऐसी विकट परिस्थिति में संशोधन कैसे संभव है हम संविधान संशोधन के पक्ष में आंदोलन प्रारंभ कर रहे हैं किन्तु आप विचार करिये कि क्या आप धर्म निरपेक्षता और समान नागरिक संहिता का समर्थन करेंगे। क्या आप हिन्दू राष्ट्र और समान आचार संहिता की जिद नहीं करेंगे? जो लोग भारत के संविधान में हिन्दू राष्ट्र और समान आचार संहिता के पक्ष में संशोधन करना चाहते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे सहमत नहीं। जो लोग समान नागरिक संहिता और धर्म निरपेक्ष स्वरूप के पक्षधर हैं उनका मैं भरपूर समर्थन करूंगा।

## 9. श्री रामनारायण मिश्र अलीगढ़, उत्तर प्रदेश,

आपके विचार लम्बे समय से पढता रहा हूँ यद्यपि आप बहुत सीमा तक तटस्थ रहते हैं। किन्तु कही न कही आपकी सोच अन्तर्राष्ट्रीय विषयों में अमेरिका की ओर आर्थिक विषयों में पूंजीवाद की ओर तथा धर्म के मामले में हिन्दुओं की ओर झुकी हुई दिखती है। ऐसा क्यों है। क्या आप और तटस्थ नहीं हो सकते ?

**उत्तर** — मेरा बचपन से ही स्वभाव रहा है कि मैं जिसे सत्य मानता हूँ। उसे उसी रूप में प्रकट अवश्य ही करता हूँ। चाहे वह बात अन्य लोगों को कितनी भी असत्य क्यों न दिखे। लोग मुझ पर क्या आरोप लगायेंगे यह मैंने कभी परवाह नहीं की आप चाहे तो मेरे कार्यक्षेत्र में बचपन से अब तक की जीवन पद्धति का पता कर सकते हैं। लोग मुझे बहुत जिद्दी कहते हैं क्योंकि मैं दूसरों के दबाव से विचार अभिव्यक्ति के साथ कोई समझौता नहीं करता। किन्तु इसके साथ ही यह बात भी जुड़ है कि मैं ज्योंही अपने कथन की अपेक्षा दूसरों के कथन को ठीक मानता हूँ तुरंत ही अपनी सोच को संशोधित या परिवर्तित कर लेता हूँ। इस विचार परिवर्तन में मैं जरा भी हिचक नहीं करता।

आपने तीन निष्कर्ष निकाले हैं। तीनों ही वास्तव में गलत और तुलनात्मक रूप से सही हैं। मैं राष्ट्र को व्यवस्था की अंतिम इकाई नहीं मानता। मेरे विचार में राष्ट्र के उपर भी एक ऐसी इकाई होनी चाहिये जो राष्ट्रों की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगा सके। अब तक ऐसी व्यवस्था का अभाव है जो हमारी कमजोरी है। राष्ट्र की आन्तरिक व्यवस्था में भी मैं तानाशाही की अपेक्षा लोकतंत्र को और लोकतंत्र की अपेक्षा लोक स्वराज्य प्रणाली का पक्षधर हूँ। जिन देशों में लोकतंत्र के स्थान पर तानाशाही है वह तानाशाही हम सबके लिये कलंक है। हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे देशों के नागरिकों को तानाशाही से मुक्ति दिलाने की पहल करें और यदि इस पहल में कोई निस्वार्थ देश आगे आता है। तो हम उसका साथ दे या ऐसे निस्वार्थ देशों का नेतृत्व करें यदि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो अमेरिका सरीखें स्वार्थी देश ऐसी पहल करेंगे और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अमेरिका ने इराक में जो कुछ किया वह पूरी तरह गलत था क्योंकि अमेरिका की नीयत उसे मुक्त कराने की अपेक्षा अपने प्रभाव विस्तार की अधिक थी हमें अमेरिका का पूरा पूरा विरोध इस प्रकार करना चाहिये कि हम सद्दाम समर्थक गुट में न दिखें। भारत अमेरिका विरोध के नाम पर सद्दाम की तानाशाही का समर्थन करे यह न्यायाचित तो नहीं कहा जा सकता भले ही यह परिस्थितियाँ की मजबूरी हो वैसे अभी सद्दाम का समर्थन हमारा समक्ष कोई मजबूरी नहीं थी। अतः हमें अमेरिका विरोधी फ्रांस जर्मनी जैसे देशों का समर्थन करना चाहिए था न कि लोकतंत्रीय अमेरिका विरोधी तानाशाह सद्दाम का मैं अमेरिका की विस्तारवादी नीतियों का घोर विरोधी हूँ और तानाशाही व्यवस्था का तो उससे भी अधिक मैं अमेरिका विरोध के नाम पर तानाशाहों के समर्थन का पहले भी विरोधी था और आज भी हूँ। इराक युद्ध के समय मेरे अनेक अमेरिका विरोधी सर्वोदयी मित्रों का आक्रोश भी झेलना पड़ा था किन्तु अब भी मैं स्वयं को ठीक और उनको गलत मानता हूँ। आर्थिक विषयों में भी मेरी सोच बिल्कुल साफ है। मैं सरकारीकरण और व्यवसायीकरण के बीच सरकारीकरण को अधिक घातक मानता हूँ। व्यवसायीकरण यदि स्वच्छन्द हो जाय तो आर्थिक केन्द्रोत्थरण का घातक परिणाम होता है किन्तु सरकारीकरण का परिणाम उससे भी कई गुना अधिक घातक होता है। हम सत्ता और धन दोनों के विकेन्द्रोत्थरण के पक्षधर हैं किन्तु हम धन के विकेन्द्रोत्थरण के नाम पर सत्ता के केन्द्रोत्थरण का समर्थन तो नहीं कर सकते। हमें सत्ता और धन दोनों के विकेन्द्रोत्थरण की पहल करनी चाहिये और यदि हम ऐसी पहल नहीं करते तो व्यवसायीकरण धीरे धीरे सरकारीकरण को निगल जायेगा और हम कुछ नहीं कर पायेंगे क्योंकि व्यवसायीकरण की अपेक्षा सरकारीकरण अधिक घातक है। मुझे आश्चर्य होता है कि भारत में शिक्षा तक के सरकारीकरण की जोरदार वकालत हो सकती है जबकि हमारी शिक्षा के गुणात्मक आर संख्यात्मक विकास में सरकारीकरण सबसे अधिक बाधक है। शिक्षा के पूरा व्यवसायीकरण के जो दुष्परिणाम आते वे सरकारीकरण के दुष्परिणाम से कम होते। मैं पूर्व में भी सरकारीकरण के स्थान पर भी आर्थिक विकेन्द्रोत्थरण का पक्षधर हूँ। भारत वर्तमान जो भी आर्थिक समस्याएँ हैं आर्थिक असमानता को छोड़कर वे सब सरकारीकरण के दुष्परिणाम हैं यदि सरकारीकरण के स्थान पर नियंत्रित व्यवसायीकरण की नीति होती तो भारत में आर्थिक असमानता सहित गरीबी बेरोजगारी आदि का बेहतर समाधान संभव था। धर्म के मामले में भी स्पष्ट हूँ। मेरे विचार में हिन्दू एक जीवन पद्धति है और इस्लाम एक संगठन। हिन्दू गुणात्मक विस्तार को महत्वपूर्ण मानता है और



इस्लाम संख्यात्मक विस्तार को। मैं पूरी तरह हिन्दू जीवन पद्धति को आदर्श मानता हूँ यदि धर्म के आधार पर समाज में चार विभाजन हो तो मैं कट्टरवादी मुसलमानों को नष्ट कट्टरपंथी हिन्दुओं को आदर्श मानता हूँ। मेरे विचार में अभी दो गिरोह बने हुए हैं। (1) संघ परिवार समर्थक (2) संघ परिवार विरोधी। दोनों के राजनैतिक उद्देश्य हैं। एक अपने राजनैतिक उद्देश्यों के लिये राष्ट्र और भारतीय संस्कृति की खाल ओढकर हिन्दू चापलूसी करता है। मैं पूरी तरह धर्म निरपेक्षता का पक्षधर हूँ। मैं भारत के सभी शान्तिप्रिय धर्म प्रेमियों को एक मंच में लाना चाहता हूँ किन्तु यदि तात्कालिक रूप से किसी एक को चुनना हो तो मैं इस्लाम को विचारधारा के रूप में हिन्दुओं कि अपेक्षा अधिक कट्टर समझता हूँ। मैं संघ परिवार रहित हिन्दुत्व का पक्षधर हूँ। उपरोक्त तीनों प्रश्न पर मैंने अपने विचार स्पष्ट किये हैं। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। लोक स्वराज्य मंच के विचार भिन्न भी हो सकते हैं। पाठका से विचार मंथन के बाद इन निष्कर्षों के बदलाव भी हो सकता है किन्तु अब तक मेरे विचार यही हैं।

## 10. श्री के. आर. डडसेना, विनोबानगर मुगेली, छत्तीसगढ़

मैंने आपके पास एक पोस्टर भेजा था जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले तीस करोड़ लोगों के जीवन में सुधार के लिए अपने प्रयत्नों की रूपरेखा थी हमें इन लोगों के विकास को दिशा में कुछ करना चाहिये क्योंकि अहिंसक जन आन्दोलन की दिशा में यह वर्ग सहायक बन सकता है। हम सब लोग इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। आपका मार्गदर्शन चाहिये।

**उत्तर** — मैं आपकी योजना में कई खामियाँ देखता हूँ।

(1) शासन को कभी भी व्यक्ति को इकाई नहीं बनाना चाहिए परिवार को इकाई बनाना अधिक सुविधा जनक है। परिवार इकाई बनाने के पूर्व हमें परिवार की परिभाषा और संरचना भी स्पष्ट करनी होगी। यह सब करना चाहिए। इससे रोजगार का असंतुलन घटेगा।

(2) गरीबी रेखा बनाने की वर्तमान व्यवस्था बहुत दोषपूर्ण है। भारत में करीब एक प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जो बिल्कुल विपन्न हैं। ये परिवार या तो अभाव ग्रस्त हैं या बेरोजगार ये श्रम कर नहीं पाते। इनका जीवन स्तर बिल्कुल ही खराब है या तो भीख मांग कर गुजारा करते हैं या आधा अधूरा ही खाकर रहते हैं। इनके छोटे-छोटे बच्चे भी जंगल से दातुन या पत्ता तोड़कर बाजार में बेचते हैं या सड़कों पर पड़ प्लास्टिक टुकड़े इकट्ठे करते मिल जाते हैं। तीस प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन वस्त्र रोजगार का अभाव है और शेष गरीबी रेखा के उपर है। हम गरीबी रेखा के नीचे जो भी प्रयास करते हैं वह तीस प्रतिशत विपन्नों के जीवन स्तर में तो कुछ सहायक है किन्तु एक प्रतिशत विपन्नों के जीवन स्तर को तीस प्रतिशत लायक भी नहीं बना पाता हमारी नीतियाँ दो प्रकार की होनी चाहिए 1. एक प्रतिशत विपन्न परिवारों को भोजन, वस्त्र की ऐसी प्रत्यक्ष सहायता को वे विपन्नता से मुक्त हो सकें। तीस प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष सहायता कुछ नहीं किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी नीतियाँ बने कि श्रम मूल्य बहुत बढ़ जावे।

शिक्षा में सहायता अनाज में सबसीडी रोजगार के अवसर या लघु उद्योग प्रोत्साहन आदि सारे प्रयास षडयंत्र हैं। गरीबी रेखा के नीचे के अधिकांश लोगों का जीवन स्तर सिर्फ एक ही तरीके से सुधर सकता है और वह है श्रम मूल्य वृद्धि। गरीबी रेखा के नीचे वालों में करीब अस्सी से नब्बे प्रतिशत लोग श्रम प्रधान हैं और पांच से दस प्रतिशत बुद्धि प्रधान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लघु उद्योग आदि के सारे प्रोत्साहनों का लाभ या तो ये पांच प्रतिशत बुद्धि जीवी उठाते हैं या उपर के लोग। यह सब बहुत बड़ा षडयंत्र है। गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले को चक्को चलाने में पच्चीस प्रतिशत की छूट जो करीब पांच सौ रुपये है और गरीबी रेखा से उपर वाले को आटा मिल लगाने में भी पच्चीस प्रतिशत की छूट जो करीब तीन लाख हैं दी जाती है। गरीब को लाठी और अमीर को बन्दूक देकर प्रतिस्पर्धा के लिये छोड़ा जाता है। मेरे विचार में इसे बिल्कुल बन्द कर दें मैंने एक बार अपने एक मित्र से पूछा था कि यदि मेरे पास एक किलो अनाज है सत्तर प्रतिशत लोग भरे पेट हैं तीस प्रतिशत आधे पेट हैं और इन तीस प्रतिशत में से एक प्रतिशत बिल्कुल भूखे हैं हमें एक किला अनाज तीस प्रतिशत में बाटना चाहिए या एक प्रतिशत में आज हमारी सरकार की जो भी शक्ति है मान लीजिये कि वह सौ करोड़ रुपये को है। तो उसे वह शक्ति तीस करोड़ लोगों को उपर उठाने में लगानी चाहिए या एक करोड़ के मैं तो अन्तिम रूप से नतीजा निकाल चुका हूँ कि श्रम को मांग बढ़े और श्रम का मूल्य बढ़ यही एकमात्र इलाज है। अन्य सारी सुविधा बन्द कर दें।

आप गरीबी रेखा के नीचे वालों को व्यवस्था परिवर्तन हेतु वर्ग के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। मैं ऐसे किसी वर्ग निर्माण के पक्ष में नहीं ऐसा वर्ग निर्माण समाज में टूटन पैदा करेगा। अतः आपस निवेदन है कि ऐसे प्रयत्न की सलाह न दें।

## 11. श्री कालीचरण प्रेमी ए 106 बाग कालोनी सेक्टर 16 शास्त्रीनगर गाजियाबाद 201002

मानवाधिकार संबंधी आपके बेबाक विचारों ने बहुत प्रभावित किया आप मुसलमानों के कट्टरता की बातें ता करते हैं किन्तु भारत में जातीय उत्पीड़न की घटनाएँ घट रही हैं। दलित उत्पीड़न आम बात हो गई है। सामूहिक नरसंहार भी हो ही रहे हैं। दलित महिलाओं से बलात्कार सवर्ण हिन्दू ही करते रहे हैं। हिन्दू कट्टरता तो और भी वीभत्स है। जाति और वर्ण को खतम किये बिना इसका सुधार संभव नहीं फिर भी आप इस विषय में मान रहते हैं।

आप आरक्षण को समाप्त करने के पक्षधर हैं। अब तक दलित इतने सबल नहीं हुए कि वे सवर्णों के सामने सिर उठाकर जी सकें। अब भी सवर्ण दलितों को कीड़ मकोड़े से अधिक नहीं मानते। सवर्ण कभी दलित को सम्मान नहीं देगा। क्या आप आरक्षण समाप्त करने की इसीलिये वकालत करते हैं कि भारत में फिर से ब्राह्मणवाद हावी हो जावे। आप यह क्यों नहीं सोचते कि स्वतंत्रता के बाद दलितों और महिलाओं के साथ अत्याचारों में इस तरह लगातार बढ़ात्तरी का कारण क्या है?

उत्तर — यह सच है कि ज्ञानतत्व में साम्प्रदायिकता पर अधिक चर्चा हुई और जातीय संकीर्णता पर बहुत कम। क्योंकि इस संबंध में कोई प्रश्न आये नहीं और मैं पहल नहीं किया। आपके प्रश्नों ने यह विषय खोल दिया है।

व्यक्ति के आचारण दो प्रकार के हैं 1. व्यक्तिगत 2. सामाजिक। व्यक्तिगत आचरण में सभी वर्गों में समान स्थिति है मुसलमानों में भी अपराध प्रवृत्ति वाला को प्रतिशत वही है जो हिन्दुओं में या आदिवासियों और दलितों में महिलाओं में भी कोई अधिक अन्तर नहीं होता है। मुसलमानों में ईमानदार दयालु या कार्यकर्ता प्रायः ऐसा कहते पाये जाते हैं कि मुसलमान अधिक अपराध करते हैं किन्तु मेरे विचार से यह बात सच नहीं है। अपराध व्यक्तिगत प्रवृत्ति है। उसका धर्म, जाति या लिंग से कोई संबंध नहीं अपराधों का धर्म, जाति या लिंग से सिर्फ इतना ही संबंध है कि उनकी अपराध क्षमता क्या है। यदि वह समाज में सामाजिक या आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो कम अपराध करता है और मजबूत है तो अधिक।

किन्तु धार्मिक मामलों में मुसलमान बहुत कट्टर हो जाता है। उस समय वह न्याय और मानवता की कोई परवाह नहीं करता जबकि हिन्दू धार्मिक मामलों में पूरी तरह उदार होता है। जाति के मामले में हिन्दुओं में पूरी तरह उदार होता है जाति के मामले में हिन्दुओं में सवर्ण और दलित में बहुत अन्तर आ जाता है सवर्ण व्यक्ति स्वभावतः अपने को श्रेष्ठ मानता है और जब उसकी श्रेष्ठता को चुनौती मिलती है तो वह आक्रामक हो जाता है। यह विकृति बहुत पुराने समय से चले आ रहे जातीय आरक्षण का दुष्परिणाम है जिसमें ब्राह्मण का लडका जन्म से ब्राह्मण बनकर पूज्य बन गया। हजारों वर्षों के जातीय आरक्षण ने समाज में विकृति भी पैदा की और सामाजिक भेदभाव भी पैदा किया। यह विकृति सवर्णों की व्यक्तिगत प्रवृत्ति नहीं थी बल्कि सामाजिक संस्कार था। सवर्णों की मजबूत स्थिति ने उसे दलितों पर अत्याचार के अवसर भी प्रदान किये।

इस समय का सबसे अच्छा इलाज स्वामी दयानन्द ने किया जिन्होंने वर्ग संघर्ष को बिना हता दिये ही जाति प्रथा पर अकुश लगाया अनेक दलित समाज में ब्राह्मण बनने लगे पुरानी जातीय संकीर्णता के विरुद्ध बड़ा मात्रा में सवर्ण आगे आने लगे और जातीय कट्टरता को सफल चुनौती मिली। इसी बीच कुछ दलित नेताओं की जल्दबाजी ने सामाजिक आरक्षण के विरुद्ध संवैधानिक आरक्षण की व्यवस्था करा ली। मरणासन्न जातिवाद फिर जीवित हुआ आर्य समाज के प्रयत्न असफल हुए। कर्म अनुसार जाति के स्थान पर जन्म अनुसार जाति प्रधान हो गई जो दलित कर्म अनुसार पण्डित का सम्मान पाने लगे थे उनकी सन्तान भी पुनः दलित हो गई वर्ग विद्वेष बढ़ते बढ़ते वर्ग संघर्ष तक चला गया मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि यदि सन सैंतालीस में जातीय आरक्षण न देकर सबको समान रूप से समरस होने दिया जाता तो अब तक जातिवाद बहुत कम हो जाता। यह बात सच है कि यदि आरक्षण नहीं होता तो निम्न वर्ग के लोग शासकीय नौकरी राजनीति या अन्य उच्च पदों पर बहुत कम बैठ पाते। पिछले पचास वर्षों में आरक्षण के कारण यदि सात आठ प्रतिशत दलित परिवार उपर उठ सके हैं तो बिना आरक्षण के ऐसे लोगों की संख्या एक प्रतिशत से उपर नहीं जाती किन्तु जिस तरह पूरे भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ा और जिस तरह जातीय उपनाम बदल रहे थे उससे जातीय पहचान समाप्त होना अधिक आसान हो रहा था जिसमें जातीय आरक्षण ने रोक लगा दी।

आपका कथन है कि स्वतंत्रता के बाद दलितों और महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। दलितों के साथ कीड़े मकोड़े सा व्यवहार हो रहा है। तो क्या हम मान लें कि आरक्षण पूर्व व्यवस्था वर्तमान व्यवस्था से अधिक अच्छी थी मेरे विचार में ऐसा नहीं है। आपने स्थिति को भयावह बताने का प्रयत्न किया है। जातीय दलितों के साथ न्याय किया है। उससे कई गुना अधिक समाज में जातिवाद को मजबूत किया है या समाज में वर्ग संघर्ष बढ़ाया है।

मैंने बहुत सोचा कि यदि आरक्षण नहीं होता तो एक प्रतिशत दलित भी उपर नहीं उठ पाते और हुआ तो उत्थान के साथ साथ वर्ग संघर्ष लेकर आया। कुल पांच से सात प्रतिशत दलित परिवार आरक्षण के कारण उठ पाये। शेष तो अब भी वही के वही है यदि आरक्षण और पचास वर्ष जारी रहा तो ये पांच सात प्रतिशत और उपर उठते रहेंगे। एक दो प्रतिशत इनकी संख्या और बढ़ सकती है। पांच सात प्रतिशत दलितोत्थान के लिये वर्ग संघर्ष कितना उचित नहीं है यह विवाद का विषय है किन्तु यह विवाद का विषय नहीं कि यदि श्रम मूल्य वृद्धि होती तो बड़ा संख्या में दलितोत्थान संभव था। दलित वर्ग सामाजिक आरक्षण के परिणाम स्वरूप श्रम निर्भर होता गया और सवर्ण धन और वृद्धि निर्भर। स्वतंत्रता के बाद की संवैधानिक व्यवस्था ने बुद्धि का मूल्य बढ़ाया और उसमें दलितों को आरक्षण दे दिया। शासकीय कर्मचारियों के वेतन वास्तविक श्रम मूल्य से पांच से दस गुने तक अधिक करके उसमें दलितों को आरक्षण देने से कुछ बुद्धि प्रधान दलित तो लाभान्वित हो गये किन्तु शेष श्रम प्रधान दलित वही के वही रह गये। बुद्धि का मूल्य बढ़ाने में सवर्ण भी सहमत थे क्योंकि आरक्षण के अतिरिक्त तो सारा लाभ उन्हीं का होना था यदि बुद्धि का मूल्य न बढ़ाकर श्रम जीवी लाभान्वित होता जिसका अधिकांश लाभ दलित आदिवासी या पिछड़ों को मिलता। इतना अवश्य है कि पांच सात प्रतिशत बुद्धिजीवी दलित जो आज दलित आरक्षण के नाम पर लाभ उठा चुके हैं वे पिछड़ ही रह जाते। साथ ही आरक्षण के दुष्परिणाम स्वरूप वर्ग विद्वेष भी नहीं फैलता सामाजिक आरक्षण ने जो समस्या समाज में पैदा की है उसका

समाधान न तो संवैधानिक आरक्षण था न है। इसका तो सिर्फ एक ही समाधान है श्रम की मांग बढ़ श्रम का मूल्य बढ़ और श्रम का सम्मान बढ़ सरकारी नौकरियों या राजनैतिक पदों की मांग बढ़ मूल्य बढ़े सम्मान बढ़े और आरक्षण देकर दलितोत्थान का ढिंढोरा पीटा जाय यह नीति दलित विरोधी है। श्रम विरोधी है और आत्मघाती भी है।

आज भारत में ग्यारह समस्याएँ बढ़ रही हैं। जब समाज की अस्मिता ही संकट में है तो हम ग्यारह समस्याओं की पहले चिन्ता करें कि आपके सामाजिक न्याय की। समाज में भ्रष्टाचार चरित्र पतन हिंसा और आतंक बढ़ता रहे और आपके दलितोत्थान की सबसे पहले चिन्ता की जाये यह मेरी समझ के बाहर है। यदि समाज सुरक्षित रहेगा तो दलितोत्थान हो जायेगा और यदि समाज ही संकट में चला गया तो न दलित बचेगा न सवण। घर के चूहों से परेशान होकर घर को आग लगने से प्रसन्न होना कई बुद्धिमानी नहीं शासकोय कर्मचारियों और राजनेताओं की पद प्रतिष्ठा और वेतन भत्तों में कमी करके सम्पूर्ण आरक्षण को बिल्कुल समाप्त कर दीजिये श्रम की मांग मूल्य और सम्मान का तीव्र गति से बढ़ने दीजिये तथा अपनी अधिकतम शक्ति दलितोत्थान महिला उत्थान आदिवासी उत्थान आदि भ्रामक नारों से हटाकर ग्यारह समस्याओं के समाधान में लगा दीजिये तो दलितोत्थान महिला उत्थान आदिवासी उत्थान तो स्वतः ही हो जायेगा समाज भी सुरक्षित हो जायेगा।

## लोक स्वराज्य मंच समाचार

लोक स्वराज्य मंच के अम्बिकापुर कार्यालय के साथ साथ दिल्ली कार्यालय भी बहुत सक्रिय हो गया है। लोक स्वराज्य मंच के संगठन सचिव का काम करने के लिये दो मित्रों ने फिलहाल एक वर्ष तक के लिये पूरा समय देने की घोषण की है। (1) श्री पुष्पेन्द्र चौहान दिल्ली तथा (2) श्री आनन्द गुप्त अम्बिकापुर। वर्तमान में चौहान जी दिल्ली कार्यालय को केन्द्र बनाकर कश्मीर, हरियाणा, उत्तरांचल, हिमांचल, पंजाब, उत्तर प्रदेश (पूर्वी छोड़कर) राजस्थान तथा गुजरात का संगठन सम्हालेंगे। आनन्द गुप्त जी महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा का संगठन सम्हालेंगे। शेष भारत के विषय में दो माह बाद विचार करेंगे। आनन्द जी अम्बिकापुर को केन्द्र बनाकर संगठन करेंगे। संगठन सचिव जाकर प्रयास करेंगे कि प्रदेश जिला या स्थानीय स्तर पर लोक स्व मंच का संगठन खड़ा हो। यदि आयोजक स्वयं या आनन्द जी के सहयोग से संगठन खड़ा नहीं कर सकेंगे। तो व एक लोक स्वराज्य सम्मेलन बुलाकर या मेरे भाषण का आयोजन करके मेरा भाषण करा सकते हैं। जिससे संगठन खड़ा होने में मदद मिल सके। आप सब साथियों से निवेदन है कि आप अपने संगठन सचिवों से समन्वय स्थापित करें जिससे संगठन का काम सुचारु रूप से चल सके।

### दिल्ली कार्यालय का पता —

आर्य भूषण भारद्वाज/पुष्पेन्द्र चौहान

बी 29 मंगल पांडे मार्ग गीताजलि पब्लिक स्कूल के

सामने भजनपुरा नई दिल्ली 110053

फोन -9811443566

### अम्बिकापुर का पता —

1. आनन्द गुप्त

बनारस चौक, अम्बिकापुर

सरगुजा (छत्तीसगढ़) -497001

मा. 09826157295

2. बजरंग लाल अग्रवाल

बनारस चौक, अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.) 497001

मा. 09425254192